(d) The total disbursements by All-India financial institutions amounted to Rs. 26,119 crores (provisional) during 1993-94 (including leasing, hire purchase, underwriting and direct subscription).

रक्सौल सीमा पर सोने की तस्करी

936. **श्री आस मोहम्मद : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान (बिहार राज्य में) भारत और नेपाल की रक्सौल सीमा पर तस्करी के कितने मामले सरकार की जानकारी में आए ;

(ख) जब्त की गई वस्तुओं और उनकी कीमत का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) रक्सौल सीमा पर तस्करी रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं ; अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) गत दो वित्तीय वर्षों के दौरा भारत-नेपाल सीमा पर रक्सौल में पता लगाए गए तस्करी के मामलों की संख्या निम्नानसार है :—

1992–93 : 214 मामले

1993–94 : 159 मामथे

(ख) सूचना विवरण में दी गई है **(नीचे देखिए)**

(ग) तस्करी-रोधी कार्य से जुड़े सीमा शुल्क के क्षेत्रीय कार्यालयों को तस्करी की सभी गतिविधियों को रोकने के लिए सतर्क कर दिया गया है : तस्करी संबंधी कार्य-कलापों को रोकने और इनका पता लगाने में लगी केन्द्रीय और राज्य सरकार की सभी एजेंन्सियों के बीच घनिष्ठ तालमेल बनाए रखा जा रहा है ।

विवरण

पकड़ी गयी मदों और उनके मूल्य का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

मद का नाम	मूल्य (लाख रुपयों में)	
	1992–93	1993–94
सोना . .	1.25	शून्य
चांदी . .	शून्य	2.26
वाहन . .	92.16	15.28
सिन्थेटिक फैब्रिक .	0.13	0.33
इलेक्ट्रोनिक सामान .	3.80	3.11
खाद्यान्न . .	2.26	0.13
दाल . .	27.86	6.89
एन0डी0पी0एस0	278.96	26.16
घड़ियां . .	शून्य	0.05
भारतीय मुद्रा .	शुन्य	1.51
नेपाली मुद्रा .	शुन्य	2.32
अन्य . .	13.13	20.94
कुल :	416.45	78.97

Extension of relief and concessions to sick public sector units

937. SHRI ASHOK MITRA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the details of the guidelines in regard to extension of relief and concessions to sick public sector units alongwith restructuring of the units under consideration of the Board for Industrial and Financial Reconstruction;

(b) whetner Government have verified complaints that individual bank have been flouting these guidelines; and

(c) if so, the measures Government propose to take to ensure that sick units in the public sector receive the